WITWAVES
JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
Vol-1 Issue-2
(International Peer-Reviewed E-Journal)
(November 2024)

उच्च शिक्षा के विशेष सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण

सचिन व्यास
सहा. प्राध्यापक - शिक्षाशास्त्र

शोध सार

यह शोध पत्र नई शिक्षा नीति 2020 के लिए संदर्भित है जो मुख्यतः शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है जो इसकी परंपरा संस्थित मूल्यों और लोकाचार में परिवर्तन लाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने को तत्पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शैक्षिक सुधारों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है क्योंकि यह मौजूदा शिक्षा प्रणाली की कमियों को दूर करती है। छात्र भारतीय विरासत और मूल्यों की गहरी समझ के साथ- साथ आवश्यक कौशल हासिल करेंगे। इससे वे आधुनिक दुनिया की जटिलताओं के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे। यह शिक्षा को सभी के लिए लाभकारी और सुलभ बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। नीति यह भी सुनिश्चित करती है कि छात्र बेहतर नौकरी के अवसरों और तैयारियों के साथ भविष्य का सामना करने के लिए तैयार हों।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक समान अवसर प्रदान करना है तथा विद्यार्थियों में ज्ञान कौशल बुद्धि और आत्मविश्वास का सर्जन कर उनके शिष्टकोण का विकास करना है। इस शोधपत्र में शोधकर्ता द्वितीयक आंकड़ों के माध्यम से जो गुणात्मक स्तरों पर आधारित है नई शिक्षा नीति की वास्तविक विशेषताओं को दर्शा ना चाहता है। उपरोक्त विश्लेषक तथ्यों के आधार पर शोधकर्ता इस शोध पत्र के माध्यम से अनेक सुझावों को प्रस्तुत करता है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए अति आवश्यक है।

बीज शब्द

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पाठ्यचर्या, उच्च शिक्षा, सर्वांगीण, व्यक्तित्व विकास, शिक्षार्थी केन्द्रित शिक्षा, वर्णनात्मक शोध।

भूमिका

भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था अमेरिका, चीन के बाद विश्व की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा शिक्षा व्यवस्था है हम सभी जानते है कि शिक्षा किसी भी समाज में चलने वाली निरन्तर प्रक्रिया है, शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास अर्थात् आन्तरिक शक्तियों के विकास, आत्मविकास एवं कौशलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एवं व्यक्ति को भी अपने अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति जागरुक भी करती है, साथ ही साथ अच्छा नागरिक बनाने में सक्षम बनाती है। शिक्षा के सम्बन्ध में महात्मा गाँधी जी ने कहा था-"शिक्षा का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है।"

डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने कहा था "शिक्षा ही व्यक्ति को निडर बनाती है, एकता का पाठ पढ़ाती है। अपने अधिकारों के प्रति जागरुक करती है और अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष करने की प्रेरणा भी देती है।". राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में 21 वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। स्वतंत्रता के बाद यह देश की तीसरी शिक्षा नीति है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा यह शिक्षा नीति लाई गई है, जिसके प्रारुप को के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया। भारत में पहली शिक्षा नीति सन 1968 और दूसरी शिक्षा नीति सन 1986 में लागू की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को तैयार करना है, जो भारत के सभी बच्चों को लाभान्वित करें और उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करें। इसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परम्परा को पुनर्जीवित कर भारत को एक विश्व गुरु बनाना है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था- "हम ऐसी शिक्षा चाहते है जिससे चरित्र का निर्माण, मन की शक्ति बढे, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकें।".यह शिक्षा नीति पहुँच, समता, गुणवत्ता, सामर्थ्य एवं कौशल दक्षता पर आधारित है। इसकी घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा भारत की ज्ञान परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों को आधार मानकर शिक्षार्थी में संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास के साथ साथ नैतिक, सामाजिक, भावनात्मक एवं मूल्यों पर आधारित पाठ्यक्रम को तैयार किया जा रहा है।

नई शिक्षा नीति 2020 पांच स्तंभों पर केंद्रित हैः वहनीयता, अभिगम्यता, गुणवत्ता, न्यायपरस्ता और जवाबदेही निरंतर सीखने की प्रकिर्या को सुनिश्चित करने के लिए। इसे समाज और अर्थव्यवस्था में ज्ञान की मांग के रूप में नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे नियमित आधार पर नए कौशल हासिल करने की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसर पैदा करना। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में महत्वपूर्ण सुधारों की मांग करती है जो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए तैयार करती हैं जिससे वो नए डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा कर सके। इस प्रकार, नई शिक्षा नीति बहु-विषयकता, डिजिटल साक्षरता, लिखित संचार, समस्या समाधान, तार्किक तर्क और व्यावसायिक प्रदर्शन पर अत्यधिक प्रभाव डालती है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना है तथा नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्राथमिक और माध्यमिक डेटा का विश्लेषण करना है। इसके अन्य मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. नई शिक्षा नीति 2020 को पेश करना।
2. नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा की मुख्य विशेषताओं को देखना।
3. उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि को दर्शाने लिए।
4. शिक्षा पर राज्य के खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 4 से बढ़ाकर 6 करने की एक झलक देने के लिए।

अनुसंधान क्रियाविधि

यह अध्ययन पाठ्य, आलोचनात्मक, मूल्यांकनात्मक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक विधियों का उपयोग करते हुए प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों के माध्यम से उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ के साथ एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में नई शिक्षा नीति 2020 के

संपूर्ण अध्ययन पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसमें एमएलए हैंडबुक ऑफ रिसर्च के 8वें संस्करण का सख्ती से पालन किया गया है।

डाटा संकलन

शोध अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से आंकड़ों का संकलन किया गया है जिसके आधार पर सम्पूर्ण शोध पत्र को विश्लेषित कर लिखा गया है।

प्राथमिक स्रोत

प्राथमिक संसाधन नई शिक्षा नीति 2020 के मूल पाठ से एकत्र किए गए हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है।

माध्यमिक स्रोत

एक माध्यमिक संसाधन एक स्रोत है जो नई शिक्षा नीति 2020 पर संदर्भ पुस्तकों सहित पुरानी या गैर-मूल जानकारी प्रदान करता है। माध्यमिक स्रोतों में जीवनी, लेखक के कार्यों के महत्वपूर्ण अध्ययन, शोध पत्र और शोध प्रबंध, शोध पुस्तकें, व्यक्तिगत साक्षात्कार, विकिपीडिया, ब्रिटानिका और अन्य वेबसाइटें शामिल हैं।

शोध विस्तार

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, की जगह ले ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है और यह नीति 2020 भारत को बदलने में सीधे प्रकार से योगदान प्रदान करती है और भारतीय लोकाचार में निहित शिक्षा प्रणाली को देखती है। इसका उद्देश्य धर्म, लिंग, जाति या पंथ के किसी भी भेदभाव के बिना, सभी को बढ़ने

और विकसित होने के लिए एक समान मंच प्रदान करना और सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके मौजूदा जीवंत ज्ञान समाज को बनाए रखना और उसकी देखभाल करना है। यह भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में भी एक कदम है। इस नीति में यह परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों के समान पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र को, छात्रों में मौलिक कर्तव्यों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करनी चाहिए और संवैधानिक मूल्यों, अपने देश और एक बदलती दुनिया के साथ एक संबंध पैदा करना चाहिए। इस नीति का दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास, बुद्धि और कर्म के साथ न केवल विचार बल्कि मूल्यों और दृष्टिकोणों में भी विकास करना है, जो मानव अधिकारों, सतत विकास और जीवन का समर्थन करते हैं और वैश्विक कल्याण के लिए एक जिम्मेदार प्रतिबद्धता, जिससे वास्तव में एक वैश्विक नागरिक प्रतिबिंबित होता है।

गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य, ऐसे व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए जो उत्कृष्ट,विचारशील और अच्छी रचनात्मक प्रवत्ति के हों। यह एक व्यक्ति को रुचि के एक या एक से अधिक विशिष्ट जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, व्यक्तिगत, तकनीकी, व्यावसायिक विषयों सहित क्षेत्रों में गहराई से अध्ययन करने और चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा भावना और 21 वीं सदी के कौशल को आवश्यक सीमा तक विकसित करने में सक्षम बनाती है। नई शिक्षा नीति वर्तमान प्रणाली में कुछ मौलिक परिवर्तन लाती है।

विभिन्न पुस्तकों के अध्ययन के फलस्वरुप उनसे संकलित तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते है कि उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दृष्टिकोण है कि छात्रों में भारतीय होने का न केवल गर्व हो न सिर्फ विचारों में बल्कि उनके व्यवहार, बुद्धि, कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यो और सोच में भी भारतीयता होनी चाहिए जिससे वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्ययन का विश्लेषण करने पर निम्न कुछ तथ्य सामने आए है -

1. यह शिक्षा नीति विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षा देने पर बल देती है जिससे छात्र-छात्रायें तार्किक एवं रचनात्मक रुप से विभिन्न विषयों को अन्तर्सम्बन्धित करके कुछ नया सोच पाये और बदलती परिस्थितियों में उसका प्रयोग कर सकें।
2. संबंधित पाठ्यक्रम के अलावा विकल्प रूप में अन्य संकाय के विषयों को पढ़ने की स्वतंत्रता भी विद्यार्थियों को दी गई है, जैसे जो छात्र इंजीनीयरिंग कर रहे है वह संगीत, साहित्य या वाणिज्य पढ़ सकते है।
3. इस शिक्षा नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है, व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित सभी प्रकार के कार्यक्रमों को विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों स्तर पर शामिल करने की बात की गई है।
4. इस शिक्षा नीति में स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एड एक्जिट व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके तहत छात्र 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरुप डिग्री या प्रमाणपत्र दिया जायेगा।1 वर्षो के बाद प्रमाणपत्र, 2 वर्षो के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षो के बाद स्नातक की डिग्री एवं 4 वर्षो के बाद शोध के साथ स्नातक।
5. उच्च शिक्षा संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3 प्रतिशत (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक का लक्ष्य रखा गया है।
6. उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त अंको या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जायेगा, ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।
7. सभी प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग होगी, इस नीति का उद्देश्य 2025 तक 50 फीसदी छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है।
8. इस शिक्षा नीति में अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शोध कार्यो को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे अन्तर्राष्ट्रीय छात्रों के लिये भारत में शोध करने एवं भारतीय छात्र जो विदेशों में जाकर शोध कार्य करना चाहते है उन्हें अवसर प्रदान किए जाएंगे।
9. इस शिक्षा नीति में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद के गठन की बात की गई है, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को

पूरा करने के लिये कई कार्य क्षेत्र होगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिये एकल निकाय का कार्य करेगा ।

निष्कर्ष

प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की समृद्ध परम्परा के आलोक यह नीति शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करने, मौजूदा शिक्षा प्रणाली में सुधार, बहु अनुशासनात्मक शिक्षा, संकल्पनात्मक समक्ष एवं नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा नीति है। इनसे रचनात्मक और नवाचार को महत्व मिलेगा समय के साथ शिक्षा नीति में परिवर्तन आवश्यक होता है ताकि देश की उन्नति सही तरीके से और तेजी से हो सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति को 34 वर्षो के बाद लाया गया है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य पालको को केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी देकर उनकी मानसिक बौद्धिक क्षमता को और भी ज्यादा प्रबल बनाना है।

शिक्षा किसी भी देश और समाज के विकास की महत्वपूर्ण आधार होता है। शिक्षा के बलबूते ही किसी भी देश का विकास तेजी से किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सन्दर्भ सूची

1. निशंक, रमेश पोखरियल/ शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण नई शिक्षा नीति 2020
2. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय /राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
3. चन्द्रशेखर, बी और धर्मराजन, श्री प्रिया/राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: चुनौतियां।
4. अरोड़ा, पंकज व शर्मा, ऊषा/राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रचनात्मक सुधारों की ओर।